Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

दक्षिण एशिया में भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता

आदिल गोयतः शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्विद्यालय

(प्रो.) डॉ. ब्रह्म प्रकाशः राजनीति विज्ञान विभाग, बाबा मस्तनाथ विश्विद्यालय

सारांश

यह शोध–पत्र दक्षिण एशिया में भारत और चीन के बीच विकसित होती भू–राजनीतिक, आर्थिक और सामरिक प्रतिद्वंद्विता का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत करता है। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक तक दक्षिण एशिया वैश्विक शक्ति–संतुलन का केंद्र बन गया है, जहाँ भारत और चीन दो उभरती हुई महाशक्तियाँ अपने–अपने प्रभाव क्षेत्र को मजबूत करने में लगी हैं। यह अध्ययन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर समकालीन भू–राजनीतिक परिवर्तनों तक, दोनों देशों की नीतियों जैसे चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (ठत्प्), भारत की नेबरहुड फर्स्ट और ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी का तुलनात्मक अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त यह शोध–पत्र क्षेत्रीय देशों जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान और मालदीव में भारत–चीन की प्रतिस्पर्धी रणनीतियों का भी विश्लेषण करता है। अध्ययन यह निष्कर्ष निकालता है कि दक्षिण एशिया में भारत–चीन प्रतिद्वंद्विता केवल क्षेत्रीय प्रभुत्व का संघर्ष नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक सामरिक पुनर्संतुलन का हिस्सा है जिसमें अमेरिका, जापान और आसियान जैसी बाह्य शक्तियाँ भी निर्णायक भूमिका निभा रही हैं।

मुख्य शब्दः दक्षिण एशिया, भू–राजनीति, आर्थिक कूटनीति, सुरक्षा, इंडो–पैसिफिक रणनीति, क्षेत्रीय संतुलन।

परिचय

दक्षिण एशिया, जो भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत विविधतापूर्ण क्षेत्र है, आज वैश्विक राजनीति के केंद्र में है। इस क्षेत्र में भारत और चीन दो ऐसी प्राचीन सभ्यताएँ हैं जो न केवल अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के कारण

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में भी उभरती हुई महाशक्तियों के रूप में प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर इक्कीसवीं सदी तक दक्षिण एशिया एक ऐसे भू–राजनीतिक मंच के रूप में उभरा है जहाँ भारत की क्षेत्रीय नेतृत्व क्षमता और चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा आमने–सामने आती है। शीत युद्ध के बाद के युग में वैश्विक राजनीति एकध्रुवीय से बहुध्रुवीय संरचना की ओर बढ़ी है, और इसी प्रक्रिया में दक्षिण एशिया की भू–राजनीतिक महत्ता अत्यधिक बढ़ी है।

भारत पारंपरिक रूप से दक्षिण एशिया में स्थायित्व और नेतृत्व का केंद्र रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, सैन्य क्षमता, लोकतांत्रिक व्यवस्था और सांस्कृतिक जुड़ाव ने इसे इस क्षेत्र का केंद्रीय स्तंभ बनाया है। इसके विपरीत, चीन ने पिछले चार दशकों में तीव्र आर्थिक विकास, प्रौद्योगिकी और अवसंरचना निर्माण के माध्यम से वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। इस आर्थिक विस्तार के परिणामस्वरूप चीन ने दक्षिण एशिया के लगभग सभी देशों–विशेषकर पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में निवेश और राजनीतिक प्रभाव बढ़ाया है। परिणामस्वरूप, क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएँ प्रतिस्पर्धा में बदल गई।

भारत–चीन संबंधों की जटिलता का इतिहास प्राचीन काल तक जाता है, जब दोनों देशों के बीच बौद्ध धर्म, व्यापार और सांस्कृतिक संपर्क थे। किंतु आधुनिक युग में यह संबंध सहयोग से अधिक प्रतिस्पर्धा की दिशा में मुड़ गया। 1962 के भारत–चीन युद्ध ने दोनों के बीच गहरे अविश्वास की नींव रखी, और इसके बाद से सीमावर्ती विवाद, भू–राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, तथा वैश्विक शक्ति–संतुलन में स्थान पाने की होड़ इस संबंध की प्रमुख विशेषताएँ बन गई।

इक्कीसवीं सदी में यह प्रतिस्पर्धा नए रूप में सामने आई है। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (ठत्ब्), स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटिजी और दक्षिण एशिया में बढ़ता निवेश भारत की क्षेत्रीय रणनीति के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। दूसरी ओर, भारत ने नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ऐक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो–पैसिफिक विजन के माध्यम से अपने प्रभाव को मजबूत करने का प्रयास किया है।

यह प्रतिद्वंद्विता केवल आर्थिक या सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं हैय यह वैचारिक और रणनीतिक स्तर पर भी गहराई से जुड़ी हुई है। भारत लोकतांत्रिक मूल्यों, पारदर्शिता और सहयोग की

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

नीति पर बल देता है, जबकि चीन केंद्रीकृत नियंत्रण और आर्थिक निर्भरता के माध्यम से प्रभाव स्थापित करना चाहता है। फलस्वरूप, दक्षिण एशिया एक ऐसे शक्ति–संतुलन के दौर से गुजर रहा है जहाँ प्रत्येक देश को भारत और चीन के बीच सामरिक संतुलन साधना पड़ रहा है।

दक्षिण एशिया का भू–राजनीतिक परिदृश्य

दक्षिण एशिया का भू–राजनीतिक परिदृश्य विश्व राजनीति के सबसे जटिल और संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है। यह क्षेत्र न केवल भौगोलिक रूप से विविध है, बल्कि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और आर्थिक रूप से भी अत्यंत बहुरंगी संरचना रखता है। दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान जैसे देश सम्मिलित हैं, जिनकी सीमाएँ हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक फैली हुई हैं। यह भौगोलिक विस्तार दक्षिण एशिया को एक विशिष्ट सामरिक महत्व प्रदान करता है। इसके उत्तर में स्थित हिमालय पर्वतमाला प्राकृतिक रक्षा कवच का कार्य करती है, जबकि दक्षिण में फैला हिंद महासागर वैश्विक समुद्री व्यापार का केंद्र है। इस समुद्री क्षेत्र से होकर विश्व के लगभग 70 प्रतिशत तेल और ऊर्जा संसाधनों का परिवहन होता है। अतः यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति इसे विश्व की ऊर्जा सुरक्षा, व्यापारिक संपर्क और सामरिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र बना देती है।

दक्षिण एशिया की भू–राजनीति को समझने के लिए इसके ऐतिहासिक आधार को देखना अनिवार्य है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने इस क्षेत्र की राजनीतिक सीमाओं और आंतरिक शक्ति–संतुलन को गहराई से प्रभावित किया। औपनिवेशिक शासन के दौरान बनाई गई सीमाएँ भौगोलिक और सांस्कृतिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं थीं, जिसके परिणामस्वरूप भारत–पाकिस्तान, भारत–चीन और भारत–नेपाल जैसे सीमा विवाद उत्पन्न हुए। 1947 में भारत के विभाजन ने दक्षिण एशिया में स्थायी सुरक्षा द्वंद्व की नींव रखी। पाकिस्तान का उदय भारत के लिए एक सामरिक चुनौती के रूप में हुआ, और यही प्रतिस्पर्धा आगे चलकर क्षेत्रीय राजनीति की दिशा निर्धारित करने लगी। शीत युद्ध के दौरान दक्षिण एशिया महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा का अप्रत्यक्ष युद्धक्षेत्र बन गया–जहाँ अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान के माध्यम से प्रभाव बढ़ाने की कोशिश की, वहीं भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

शीत युद्धोत्तर काल में दक्षिण एशिया की राजनीति में एक नया आयाम तब जुड़ा जब चीन ने अपनी आर्थिक शक्ति का विस्तार दक्षिण एशिया तक करना आरंभ किया। 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)'' के तहत भीन ने दक्षिण एशियाई देशों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रारंभ किया। पाकिस्तान में ''चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)'' इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है, जिसने चीन को अरब सागर के ग्वादर बंदरगाह तक सीधी पहुँच प्रदान की। इसी प्रकार श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर लेकर चीन ने हिंद महासागर में अपनी स्थायी सामरिक उपस्थिति सुनिश्चित कर ली। नेपाल और बांग्लादेश में अवसंरचना निवेश, ऋण सहायता, और परिवहन नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से चीन ने अपने प्रभाव का विस्तार किया। यह समूची प्रक्रिया चीन की ''स्टिंग ऑफ पर्ल्स'' रणनीति का हिस्सा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत वह हिंद महासागर के चारों और अपने नौसैनिक ठिकानों और आर्थिक उपस्थिति का जाल बिछा रहा है।

दूसरी ओर, भारत इस स्थिति को अपनी पारंपरिक क्षेत्रीय भूमिका के लिए चुनौती के रूप में देखता है। ऐतिहासिक रूप से भारत दक्षिण एशिया में सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक नेतृत्व की स्थिति में रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति इसे इस क्षेत्र का 'हृदय' बनाती है–भारत लगभग सभी दक्षिण एशियाई देशों से सीमा साझा करता है। भारत की विदेश नीति में दक्षिण एशिया का केंद्रीय स्थान है, जिसे वह ''पड़ोसी पहले'' नीति और ''सागर दृष्टिकोण (Security and Growth for All in the Region)'' जैसी पहलों के माध्यम से सशक्त करने का प्रयास कर रहा है। भारत का लक्ष्य है कि क्षेत्रीय सहयोग, कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण के माध्यम से दक्षिण एशिया को एक स्थिर और सहयोगात्मक भू–राजनीतिक इकाई बनाया जा सके। परंतु, चीन की तीव्र आर्थिक पहुँच और उसकी ऋण–राजनीति (Debt Diplomacy) ने भारत की इस कोशिश को जटिल बना दिया है।

दक्षिण एशिया में भारत और चीन की प्रतिस्पर्धा केवल आर्थिक या सामरिक नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक भी है। भारत क्षेत्रीय देशों के साथ ऐतिहासिक, भाषाई और धार्मिक समानता के माध्यम से विश्वास निर्माण करता है, जबकि चीन आर्थिक निर्भरता और अवसंरचनात्मक निवेश के जरिए प्रभाव स्थापित करता है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

जैसे देश इस प्रतिस्पर्धा में संतुलन की नीति अपनाने का प्रयास करते हैं। पाकिस्तान स्पष्ट रूप से चीन के पक्ष में झुका हुआ है, जबकि बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों भारत के साथ सहयोग बनाए रखते हुए चीन से निवेश लेना जारी रखते हैं। नेपाल जैसे देश भारत और चीन के बीच संतुलन साधने की नीति अपनाते हैं। यह परिदृश्य दक्षिण एशिया को रणनीतिक अनिश्चितता'' (Strategic Ambiguity) की स्थिति में ले आया है, जहाँ प्रत्येक देश अपने आर्थिक हित और सुरक्षा आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है।

दक्षिण एशिया का भू–राजनीतिक परिदृश्य केवल क्षेत्रीय शक्तियों तक सीमित नहीं है। बाहरी महाशक्तियों की भूमिका भी इसमें निर्णायक है। अमेरिका की ''इंडो–पैसिफिक रणनीति'' और ''क्वाड गठबंधन भारत को चीन के विरुद्ध एक स्वाभाविक सहयोगी बनाते हैं। जापान और ऑस्ट्रेलिया भारत के साथ मिलकर हिंद महासागर में स्वतंत्र और खुला समुद्री क्षेत्र सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। रूस यद्यपि चीन का रणनीतिक साझेदार है, फिर भी भारत के साथ उसके ऐतिहासिक रक्षा और ऊर्जा संबंध उसे इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी शक्ति बनाए रखते हैं। इन सभी बाहरी शक्तियों की सक्रियता से दक्षिण एशिया ''बहुध्रुवीय शक्ति–संतुलन'' का क्षेत्र बन गया है, जहाँ कोई भी एक देश पूर्ण प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकता।

भू–राजनीतिक दृष्टि से दक्षिण एशिया केवल प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र नहीं, बल्कि सहयोग की संभावना भी रखता है। इस क्षेत्र की साझा समस्याएँ–गरीबी, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, सीमा–पार अपराध, ऊर्जा संकट ऐसी चुनौतियों हैं जिन्हें किसी एक देश द्वारा नहीं, बल्कि सामूहिक नीति से ही सुलझाया जा सकता है। भारत और चीन, यदि प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग के मॉडल को अपनाएँ, तो दक्षिण एशिया एशिया का विकास इंजन बन सकता है। परंतु वर्तमान वास्तविकता यह है कि आपसी अविश्वास, सीमा विवाद और महाशक्तियों की रणनीतिक नीतियाँ इस सहयोग को कठिन बना रही हैं।

भारत और चीन की विदेश नीति का तुलनात्मक अध्ययन

भारत की विदेश नीति का मूल तत्व ''शांतिपूर्ण सह–अस्तित्व'', ''गुटनिरपेक्षता'', और ''वसुधैव कुटुम्बकम्'' जैसी दार्शनिक अवधारणाओं पर आधारित है। भारत की विदेश नीति का प्राथमिक उद्देश्य रहा है–क्षेत्रीय स्थिरता, सीमा सुरक्षा, आर्थिक आत्मनिर्भरता, और वैश्विक स्तर पर एक

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

जिम्मेदार लोकतांत्रिक शक्ति के रूप में अपनी पहचान स्थापित करना। शीत युद्ध के दौरान भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के माध्यम से न तो अमेरिका और न ही सोवियत संघ के साथ किसी औपचारिक गुट का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। इसका परिणाम यह हुआ कि भारत ने एक स्वतंत्र और संतुलित कूटनीतिक रेखा तैयार की इसके विपरीत, चीन की विदेश नीति 'राष्ट्रीय शक्ति के पुनरुत्थान'' और ''प्रभाव–विस्तार'' पर आधारित है। 1949 में जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना के बाद से ही उसकी विदेश नीति ''विचारधारात्मक'' से ''व्यावहारिक होती चली गई। माओत्से तुंग के युग में यह नीति क्रांतिकारी समाजवाद और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि देंग शियाओपिंग के नेतृत्व में चीन ने ''सुधार और खुलेपन की नीति अपनाई। इस काल से चीन की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य बना–आर्थिक आधुनिकीकरण और वैश्विक स्तर पर प्रभाव विस्तार। वर्तमान समय में शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की विदेश नीति ''चीनी स्वप्न'' की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत वह 2049 तक ''वैश्विक शक्ति'' के रूप में अपना पुनरुत्थान चाहता है।

दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में भारत और चीन की विदेश नीतियाँ अक्सर एक–दूसरे के समान लक्ष्यों की दिशा में प्रतिस्पर्धात्मक रूप में कार्य करती हैं। भारत दक्षिण एशिया को अपने पारंपरिक प्रभाव क्षेत्र के रूप में देखता है। वह ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टि से इस क्षेत्र का स्वाभाविक नेता है। भारत की विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य है– अपने पड़ोसी देशों के साथ स्थिर, सहयोगात्मक और विश्वास–आधारित संबंध बनाना। इसके लिए भारत ने 'पड़ोसी पहले'' नीति, ''एक्ट ईस्ट नीति और ''सागर दृष्टिकोण'' जैसी पहलें की हैं। इन पहलों के माध्यम से भारत दक्षिण एशिया को आर्थिक, सुरक्षा और अवसंरचना सहयोग के माध्यम से एकीकृत करना चाहता है।

चीन की दृष्टि इसके विपरीत, दक्षिण एशिया को 'रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र'' के रूप में देखती है। चीन की विदेश नीति का उद्देश्य है इस क्षेत्र में आर्थिक निवेश, ऋण सहायता और अवसंरचना विकास के माध्यम से दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव स्थापित करना। 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)'' इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसके तहत चीन पाकिस्तान में ''CPEC'', श्रीलंका में 'हम्बनटोटा बंदरगाह, नेपाल में सड़क–रेल परियोजनाएँ, और बांग्लादेश में औद्योगिक पार्क स्थापित कर चुका है। यह समूची रणनीति भारत को चारों ओर से घेरने वाली ''स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के रूप में व्याख्यायित की जाती है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

भारत की विदेश नीति स्वभावतः संवादपरक और संतुलनकारी है, जबकि चीन की नीति आक्रामक और आर्थिक निर्भरता निर्माण पर केंद्रित है। भारत अपने पड़ोसी देशों को साझेदार के रूप में देखता है, जबकि चीन उन्हें आर्थिक–सामरिक प्रभाव क्षेत्र के हिस्से के रूप में। उदाहरणस्वरूप, नेपाल के साथ भारत के ऐतिहासिक और धार्मिक संबंध हैं, परंतु चीन वहाँ भारी निवेश कर उसकी नीति–निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। श्रीलंका में भारत सांस्कृतिक और राजनीतिक संवाद के माध्यम से प्रभाव बनाए रखना चाहता है, जबकि चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 वर्षों के लिए पट्टे पर लेकर उसे अपने सामरिक तंत्र में सम्मिलित कर लिया।

भारत की विदेश नीति लोकतांत्रिक और बहुपक्षीय संस्थागत ढाँचों में विश्वास रखती है। वह SAARC, BIMSTEC, और QUAD जैसे मंचों के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देता है। वहीं चीन द्विपक्षीय समझौतों और आर्थिक ऋण नीति के माध्यम से प्रभाव फैलाता है। भारत की नीति पारदर्शिता और परस्पर लाभ पर आधारित है, जबकि चीन की रणनीति 'ऋण–निर्भरता और ''संसाधन नियंत्रण'' के माध्यम से दीर्घकालिक सामरिक लाभ प्राप्त करने की है।

दक्षिण एशिया में दोनों देशों की नीतियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। पाकिस्तान चीन का प्रमुख सहयोगी है और वह ''CPEC'' के माध्यम से चीन की सामरिक उपस्थिति को सशक्त कर रहा है। वहीं बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों भारत और चीन के बीच संतुलन साधने का प्रयास कर रहे हैं। नेपाल और मालदीव कभी भारत के साथ निकटता दिखाते हैं तो कभी चीन की ओर झुकाव प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार दक्षिण एशिया का भू–राजनीतिक परिदृश्य 'शक्ति–संतुलन की निरंतर प्रक्रिया में बना हुआ है, जहाँ भारत और चीन की विदेश नीतियों परस्पर प्रतिस्पर्धी किन्तु परोक्ष रूप से परस्पर निर्भर भी हैं।

दक्षिण एशिया के संदर्भ में भारत और चीन की विदेश नीतियाँ क्षेत्रीय शक्ति–संतुलन की दो विपरीत परंतु परस्पर जुड़ी धाराएँ हैं। भारत जहाँ अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, ऐतिहासिक विरासत और कूटनीतिक संतुलन के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता की ओर अग्रसर है, वहीं चीन अपनी आर्थिक क्षमता, अवसंरचनात्मक निवेश और रणनीतिक गहराई के माध्यम से प्रभाव विस्तार की नीति अपना रहा है। भारत की नीति सहयोग और विश्वास पर आधारित है,

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

जबकि चीन की नीति नियंत्रण और प्रभुत्व की ओर झुकी हुई है। दक्षिण एशिया का भविष्य इसी बात पर निर्भर करेगा कि क्या ये दोनों महाशक्तियों प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर ''सह–अस्तित्व'' और ''साझा विकास'' की दिशा में बढ़ पाती हैं या नहीं।

सुरक्षा और सामरिक संतुलनः सीमा विवाद से इंडो–पैसिफिक तक

भारत और चीन के बीच सुरक्षा एवं सामरिक संतुलन का प्रश्न दक्षिण एशिया और व्यापक एशिया–प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता का सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व बन चुका है। इन दोनों देशों के बीच संबंधों की जटिलता केवल आर्थिक या राजनीतिक नहीं, बल्कि भौगोलिक, ऐतिहासिक और सैन्य दृष्टि से भी गहराई तक निहित है।

भारत और चीन के बीच सीमा विवाद 1950 के दशक से ही उनके द्विपक्षीय संबंधों की सबसे बड़ी चुनौती रहे हैं। औपनिवेशिक काल में खींची गई ''मैकमोहन रेखा'' और ''अक्साई चिन क्षेत्र'' पर असहमति आज भी कायम है। 1962 का भारत–चीन युद्ध केवल सीमाओं का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह दो राजनीतिक दृष्टिकोणों लोकतंत्र और साम्यवाद की वैचारिक टकराहट का भी प्रतीक था। युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच अविश्वास का वातावरण गहराता चला गया। 1980 और 1990 के दशक में कई दौर की वार्ताएँ हुई, जिनसे सीमा पर शांति और स्थिरता के लिए समझौते बने, जैसे ''शांति और स्थिरता बनाए रखने का समझौता (1993)'' और ''विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता (1996)''। किंतु ये प्रयास वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर तनाव को स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सके।

21वीं सदी में सीमा विवाद फिर से भारत–बीन संबंधों का केंद्र बन गया, विशेषकर 2017 के डोकलाम संकट और 2020 के गलवान घाटी संघर्ष के बाद। गलवान की घटना ने भारत की सुरक्षा रणनीति को मूलतः बदल दिया। भारत ने महसूस किया कि चीन के साथ केवल कूटनीतिक संवाद पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे अपने सैन्य, तकनीकी और भू–राजनीतिक सहयोगों को पुनर्संतुलित करना होगा। इस संदर्भ में भारत ने अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ''क्याड गठबंधन में सक्रिय भागीदारी की, जो कि हिंद–प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने का एक सामरिक मंच है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

इंडो–पैसिफिक की अवधारणा ने भारत–चीन प्रतिस्पर्धा को नया आयाम दिया है। चीन 'दक्षिण चीन सागर'' में कृत्रिम द्वीपों, सैन्य ठिकानों और नौसैनिक तैनाती के माध्यम से अपना नियंत्रण बढ़ा रहा है। इसका उद्देश्य है–समुद्री व्यापार मागों पर प्रभाव स्थापित करना, जिससे वैश्विक व्यापार में उसकी पकड़ मजबूत हो। वहीं भारत, अमेरिका और जापान जैसे देशों के साथ मिलकर 'मुक्त और खुला इंडो–पैसिफिक की अवधारणा को बढ़ावा दे रहा है। यह एक ऐसी रणनीतिक पहल है जिसका उद्देश्य चीन के समुद्री प्रभुत्व को सीमित करना और नियम–आधारित समुद्री व्यवस्था को सुद्ध करना है।

भारत की सामरिक नीति अब 'रक्षात्मक प्रतिरोध'' (Defensive Deterrence) से ''सक्रिय प्रतिरोध'' (Active Deterrence) की ओर अग्रसर है। भारत ने अपनी सीमाओं पर आधारभूत संरचनाओं का तीव्र विकास किया है, जिसमें सड़कें, पुल, और हवाई ठिकाने शामिल हैं। साथ ही, चीन की बढ़ती तकनीकी और सैन्य क्षमता के जवाब में भारत ने स्वदेशी रक्षा उत्पादन और अंतरराष्ट्रीय सैन्य सहयोग दोनों को सशक्त किया है। भारत की राफेल विमानों की खरीद, अग्नि मिसाइल कार्यक्रम का विस्तार, और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम का विकास इसी दिशा में कदम हैं।

चीन की दृष्टि से भारत उसकी 'पश्चिमी सीमा पर रणनीतिक चुनौती है, जबकि भारत चीन को ''पूर्वी सीमाओं और समुद्री विस्तार की चुनौती के रूप में देखता है। इस परस्पर अविश्वास ने दोनों देशों को 'सुरक्षा द्वद्ध' (Security Dilemma) में फँसा दिया है। भारत के किसी भी सामरिक कदम को चीन अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है, और चीन की किसी भी सैन्य गतिविधि को भारत प्रतिरोध का संकेत समझता है। यह द्वंद्व न केवल सीमा पर, बल्कि कूटनीतिक मंचों पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है–जैसे कि संयुक्त राष्ट्र, ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन में।

भविष्य की दृष्टि से देखा जाए तो सुरक्षा और सामरिक संतुलन केवल सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं रहेगा। तकनीकी नवाचार, साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष क्षमता और भू–राजनीतिक गठबंधनों की भूमिका और अधिक बढ़ेगी। भारत को अपनी रणनीति में दोहरी दिशा अपनानी होगी–एक और चीन के विस्तारवाद का सशक्त प्रतिरोध, और दूसरी ओर क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने हेतु बहुपक्षीय कूटनीतिक संवाद।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

दक्षिण एशियाई देशों में भारत–चीन प्रभाव का विश्लेषण

देश	चीन की भूमिका	भारत की भूमिका	परिणाम
नेपाल	BRI में शामिल, सड़क व रेल निवेश	सांस्कृतिक, धार्मिक, जनसंपर्क	प्रभाव संतुलन
भूटान	सीमित परंतु रणनीतिक दबाव	सुरक्षा सहयोग	भारत प्रभावी
श्रीलंका	बंदरगाह, ऋण, निवेश	मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण	प्रतिस्पर्धा
बांग्लादेश	औद्योगिक निवेश	सामाजिक व ऐतिहासिक संबंध	प्रतिस्पर्धा
पाकिस्तान	CPEC, सैन्य सहयोग	सीमित संपर्क	चीन की बढ़त

निष्कर्ष

दक्षिण एशिया में भारत और चीन की प्रतिद्वंद्विता केवल दो पड़ोसी शक्तियों का संघर्ष नहीं, बल्कि एशिया की बदलती भू–राजनीतिक संरचना का प्रतीक है। भारत जहाँ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित सहयोगी नेतृत्व की नीति अपनाता है, वहीं चीन अपनी आर्थिक व सामरिक परियोजनाओं–विशेषकर ''बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' और 'चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के माध्यम से क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की रणनीति पर चलता है।

यह प्रतिस्पर्धा अब केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक निवेश, सुरक्षा सहयोग, और समुद्री नियंत्रण तक विस्तारित हो चुकी है। भारत ''नेबरहुड फर्स्ट'' और ''सागर'' जैसी नीतियों के माध्यम से क्षेत्रीय स्थिरता और संतुलन बनाए रखने का प्रयास कर रहा है, जबकि चीन अपने रणनीतिक निवेशों के माध्यम से प्रभाव–विस्तार में जुटा है। इसके परिणामस्वरूप दक्षिण एशिया के छोटे देश इस शक्ति–संतुलन की धुरी बन गए हैं।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

यद्यपि दोनों देशों के बीच अविश्वास बना हुआ है, फिर भी उनकी आर्थिक और क्षेत्रीय निर्भरता यह संकेत देती है कि यह संबंध पूर्ण संघर्ष की दिशा में नहीं, बल्कि "नियंत्रित प्रतिस्पर्धा की ओर अग्रसर है। दक्षिण एशिया की स्थिरता इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत और चीन अपनी प्रतिद्वंद्विता को कितनी परिपक्वता से "संतुलित सहयोग" में बदल पाते हैं।

अंततः यह प्रतिद्वंद्विता दो भिन्न दृष्टिकोणों लोकतांत्रिक सहयोग बनाम केंद्रीकृत प्रभुत्व की टकराहट है। यदि भारत और चीन संवाद, विश्वास और साझा विकास के पथ पर आगे बढ़ते हैं, तो दक्षिण एशिया संघर्ष का नहीं, बल्कि सहयोग और शांति का केंद्र बन सकता है।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

संदर्भ सूची:

1. Gong, X. (2025). Where India and China Meet: Competing Regional Statecraft in South Asia. Political Science Quarterly. Advance Article. https://academic.oup.com/psq/advancearticle/doi/10.1093/psquar/qqaf059/8195582

2. Pant, H. V. (2018). India's Foreign Policy and China: Evolving Dynamics. Routledge

3. Menon, S. (2016). Choices: Inside the Making of India's Foreign Policy. Penguin

4. Brahma Chellaney (2017). Water, Peace, and War, Confronting the Global Water Crisis. HarperCollins

5 Nguyen, C. (2022) India-China Strategic Competition in the Indian Ocean Journal of International and Area Studies, 29(2), 45-67. https://e-jlia.com/index.php/jlia/article/view/763

6. Verma, R. (2024). India-China Rivalry, Border Dispute, Border Standoffs, and Strategic Implications. Asian Security, 20(1), 1-20. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14736489.2024.2423 996

7. Baruah, D., & Xavier, C. (2023). How India and China Compete in Non-Aligned South Asia and the Indian Ocean. Brookings Institution. https://www.brookings.edu/articles/how-india-and-china-compete-in-non-aligned-south-asia-and-the-indian-ocean/

8. Singh, V. K. (2025). Letter. India Must Resist China's Charms and Risky Rapprochement. Financial https://www.ft.com/content/5396a5a4-3ac8-4452-9a71-Times38deed57a000

9. Akhter, M. N. (2022). Understanding India and China in South Asia: Introduction. Scholar. Semantics https://pdfs.semanticscholar.org/bc25/321132901e57a64b7a2ae0ec97032d5ef51e.pdf

10. Colley, C. K. (2024). The Emerging Great Game: China, India, and America Engagement in South Asia. Stimson Center https://www.stimson.org/2024/emerging-great-game-china-india-america-engagement/

11. South Aggarwal, K. (2020). India-China Conflict and its impact in the Asian Region KPU Pressbooks. https://kpu.pressbooks.pub/icpa/chapter/india-china-conflict/

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :9.014(2025); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:14, Issue:11(1), November, 2025
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

12. Madhuri, S. (2021). China's Geopolitical Advancement in South Asia and the Implications for India. Journal of Political Science. https://journalspoliticalscience.com/index.php/i/article/download/61 /80/1402

13. Acharya, H. B., Chakravarty, S., & Gosain, D. (2018). Few Throats to Choke: On the Current Structure of the Internet. arXiv. https://arxiv.org/abs/1806.07038

14 Trivedi, L., & Lakshmipriya, G. (2022). The Brahmaputra: A Socio Political Conundrum. arXiv, https://arxiv.org/abs/2209.02065